C M Y K

20.03.2018 रायगढ़,
मंगलवार,चैत्रशुक्ल 3
पृष्ठ 8, मूल्य 3

SJU Social Justice Union

साप्ताहिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी - अधिकार से न्याय तक जल्द दैनिक हो रहा है। जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराए, सभी सम्मानीय पाठकों को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी की बधाईयाँ। // कृते सम्पादक //

Web: www.nyaysakshi.com 3 में देखें ... मोदीजी देश फिर बदल रहा है ... 6 में देखें ... दबंग ने मेरे लिए बैकफायर का .... » वर्ष-2 » अंक - 13 »

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

वैश्विक व्यापार स्पर्धा में मजबूत नहीं भारत की स्थितिः एसोचैम

नई दिल्ली,(आरएनएस)। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते विवाद के कारण वैश्विक व्यापार युद्ध की संभावना प्रबल होती जा रही है लेकिन इस युद्ध में भारत की स्थिति मजबूत नहीं होगी क्योंकि यहां आयातित अधिकतर वस्तुएं जरूरतों को पूरा करने वाली हैं। उद्योग संगठन एसोचैम के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर आयात शुल्क लगाने और अन्य उत्पादों पर भी आयात शुल्क लगाने की चेतावनी देने का चीन, यूरोप और जापान ने कड़ा विरोध किया है। जहां तक इस विवाद में भारत की स्थिति की बात है तो हम चाहें भी तो बिना तकलीफ में आए इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि यहां आयातित वस्तुएं जीवन के लिए जरूरी हैं। भारत का आयात निर्यात से कहीं अधिक है लेकिन इसके बावजूद वह वैश्विक व्यापार युद्ध में मजबूत स्थिति में नहीं है। आयात अधिक होने के बावजूद हम इसकी धमकी नहीं दे सकते हैं और इसका प्रभाव हमारे निर्यात पर पड़ेगा। देश का वार्षिक व्यापार घाटा लगभग 150 अरब डॉलर का है। चालू वित्त वर्ष में आयातित वस्तुओं का बिल 450 अरब डॉलर के पार जा सकता है जबकि निर्यात लगभग 300 अरब डॉलर का है। आयातित वस्तुओं में एक चौथाई हिस्सा कच्चे तेल और उससे संबंधित वस्तुओं का है। इसके बाद प्लास्टिक और खाद का आयात होता है और अगर इनका आयात बंद किया जाए तो देश के पास इतनी उत्पादन क्षमता नहीं कि जरूरतों को पूरा किया जा सके। संगठन के अनुसार, व्यापार युद्ध की आशंका के तेज होने से पहले ही फरवरी में स्टील आयात 21 प्रतिशत की वार्षिक बढ़त के साथ 1.15 अरब डॉलर रहा और अलौह धातुओं का आयात 33 प्रतिशत बढ़कर एक अरब डॉलर का रहा। भारत को स्टील आयात में आये तेज उछाल पर ध्यान देना होगा क्योंकि यहां घरेलू उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। ऐसे ही हालत कोयला और अन्य संबंधित उत्पादों की है जिनका घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

एनडीए ने आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय किया

अमरावती। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि एनडीए ने आंध्र प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है। एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पर साजिश रचने और अपराधियों की मदद करने का भी आरोप लगाया था। नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (तेदपा) शुक्रवार को ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग हुई थी।

लगा चुके कई आरोप : तेदेपा पोलित ब्यूरो के सदस्यों के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस के दौरान नायडू भाजपा पर तेदेपा के प्रतिद्वंद्वियों का इस्तेमाल कर पार्टी को कमजोर करने और राज्य को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने का आरोप लगा चुके हैं. तेदेपा सूत्रों के अनुसार, नायडू ने आरोप लगाया कि भाजपा एक तरफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण की मदद से नाटक चला रही है. नायडू का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के महासचिव विजय साई रेड्डी पीएमओ के चक्कर लगा रहे हैं जिससे तेदेपा और राज्य के खिलाफ साजिश का पता चलता है।

पीएमओ पर उठाए सवालः चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगमोहन रेड्डी और विजय साई रेड्डी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ए1 और ए2 से मुलाकात कर पीएमओ लोगों को क्या संदेश देना चाहता है. उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पर भाजपा के इशारे पर काम करने के अपने आरोप को दोहराते हुए कहा था कि पीएमओ में यह आर्थिक मुजरिम क्या कर रहे हैं?

आंध्र के खिलाफ साजिशः तेदेपा प्रमुख का कहना है कि आंध्र प्रदेश के खिलाफ साजिश रची गई है और इसमें शामिल लोगों को जनता के क्रोध का सामना करना होगा. जन सेना प्रमुख पवन कल्याण द्वारा तेदेपा की आलोचना का हवाला देते हुए नायडू ने कहा कि जो व्यक्ति चार साल तक चुप रहा, उसने अचानक उठकर भाजपा और मोदी पर सवाल उठाने के बजाए उनकी पार्टी के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि जन सेना प्रमुख ने वाईएसआर कांग्रेस के साथ साठगांठ की है.

यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

शिमला,(आरएनएस)। बॉलिवुड अभिनेता जितेंद्र को बड़ी राहत देते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी एक रिश्तेदार की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पुलिस ने जितेंद्र की रिश्तेदार की शिकायत पर 16 फरवरी को उनके खिलाफकेस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जनवरी 1971 में एक होटल में उसका यौन उत्पीड़न किया गया। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 मई तय की है। जितेंद्र ने अपने खिलाफदर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है और प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है।

बैंकों में पड़े 11,300 करोड़ रुपये का कोई दावेदार नहीं

नई दिल्ली,(आरएनएस)। देश के 64 बैंकों में तीन करोड़ खाताधारकों के खाते में 11 हजार 302 करोड़ की धनराशि पड़ी हुई है। जिसका कोई दावेदार ही नहीं है। इसका खुलासा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) की रिपोर्ट में हुआ है। 64 बैंकों में तीन करोड़ खाताधारकों के खाते में 11 हजार 302 करोड़ की धनराशि पड़ी हुई है। जिसका कोई दावेदार ही नहीं है। इसका खुलासा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) की रिपोर्ट में हुआ है। सबसे ज्यादा 1262 करोड़ की धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी है । वहीं पीएनबी में 1250 करोड़ है। जबकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 7040 करोड़ बचा है। यह सब धनराशि भारतीय बैंकों में कुल जमा सौ लाख करोड़ का ही अंश है। आईआईएम में आरबीआई के पूर्व चेयर प्रोफेसर बी चरण सिंह कहते हैं कि जन जमाराशियों में सबसे ज्यादा मृतकों और कई खाताधारकों के अंश शामिल हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 29 के तहत सभी बैंकों को हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर आरबीआई को रिपोर्ट देनी होती है, जिसमें दस साल से संचालित न होने वाले खातों के बारे में सूचना देनी होती है। मगर सेक्शन 26 ए यह भी कहता है कि दस या अधिक साल से खाते का संचालन न होने पर भी खाता संचालन से किसी को न तो रोका जा सकता है और न ही धनराशि का भुगतान करने से इंकार किया जा सकता। बैंकिंग कानून(संशोधन) अधिनियम 2012 के तहत शिक्षा औरऔर जागरूकता के मद में ये धनराशि पड़ी हुई है। निजी क्षेत्र की बात करें तो एक्सिस, डीसीबी, एचडी एफ सी,आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा और यस बैंक में कुल 824 करोड़ की लावारिस धनराशि पड़ी हुई है। 12 अन्य प्राइवेट बैंकों में 592 करोड़ पड़े हैं। इस प्रकार देखें तो कुल प्राइवेट बैंकों में 1416 करोड़ की धनराशि का कोई दावेदार नहीं है। प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा 476 करोड़ आई सी आई सी आई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में 151 करोड़ की धनराशि डंप है। 25 विदेशी बैंकों में भी 332 करोड़ रुपये की धनराशि है, जिसका कोई दावेदार नहीं है।

दिशाहीन और व्यक्तिगत है मोदी की विदेश नीतिः शर्मा

नई दिल्ली,(आरएनएस)। कांग्रेस के महाधिवेशन में रविवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी विदेश नीति के मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। मोदी पर व्यक्तिगत विदेश नीति पर अमल करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि वर्तमान सरकार बड़े देशों के साथ भारत के संबंधों को नहीं संभाल पाई है और विदेश नीति दिशाहीन हो चुकी है। उसने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पाकिस्तान, चीन और दूसरी चुनौतियों से निपटने में नाकाम रही है। कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में कांग्रेस ने विदेश नीति पर पेश प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिंह राव के समय की विदेश नीति की तारीफ की। साथ ही उसने मोदी सरकार की विदेश नीति पर जमकर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की तरफ से पेश प्रस्ताव में कहा गया, कि विदेश नीति हमेशा मजबूत राष्ट्रीय सहमति के साथ तालमेल बिठाकर चलती रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने इसे बाधित कर दिया और गलत सलाह पर आधारित उसके कदमों ने राष्ट्रीय सहमति को भंग कर दिया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत विदेश नीति पर अमल किया है। वर्तमान में सरकार की विदेश नीति प्रधानमंत्री के विदेश दौरे और सिर्फ लेन-देन तक सीमित रह गई है। कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया, स्पष्टता का यह नजरिया है कि भाजपा सरकार की विदेश नीति दिशाहीन है और पाकिस्तान के प्रति इसकी नीति त्रासदीपूर्ण है। इस नीति की समीक्षा की जानी चाहिए और कोई भी सफल नीति वर्तमान परिस्थितियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देते हुए एक राष्ट्रीय सहमति पर ही आधारित हो सकती है। वहीं चीन के साथ संबंधों के मामले में कांग्रेस ने कहा कि भारत और चीन के बीच एक जटिल और बहुत ही सावधानी बरते जाना वाला संबंध कायम है, क्योंकि चीन एक बड़ा पड़ोसी मुल्क है और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी भी है। एक प्रमुख शक्ति के तौर पर चीन का तेजी से उभरना भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। चीन के प्रति हमारे रवैये में सिर्फव्यवहारवाद ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें यथार्थवाद भी झलकना चाहिए। हमारा प्रयास दोनों देशों के बीच मौजूद विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। इससे पहले मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए देश की इकॉनमी को बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि सीमा पार आतंकवाद और जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का वह अभी तक हल नहीं निकाल पाई है। कांग्रेस के बीजेपी पर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी से साफहै कि अपने महाधिवेशन के जरिए उसने बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।

कांग्रेस के महाधिवेशन में प्रस्ताव

बड़े देशों से संबंध कायम रखने में नाकाम सरकार

कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, सरकार बड़े देशों के साथ संबंधों को सही ढंग से नहीं संभाल पाई है। उसकी विदेश नीति को लेकर भ्रम की स्थिति है और इसमें दृष्टि और दिशा का अभाव है। प्रधानमंत्री द्वारा अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की उपेक्षा करने की प्रवृति और आजादी के बाद भारत की उपलब्धियों को झुठलाने की प्रवृति ने विदेशों में भारत की साख घटा दी है। यह दौर अनिश्चितताओं से भरा है और इसमें अप्रत्याशित बदलाव आने वाले हैं। इससे हमारी विदेश नीति के सामने जटिल चुनौतियां आ गई हैं।

मनमोहन सिंह ने हटाई गरीबी तो भाजपा ने बढ़ाई

कांग्रेस के महाधिवेशन में रविवार को जहां एक तरफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी मोदी सरकार पर खूब बरसे। भाजपा पर गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए चिदंबरम ने मनमोहन सिंह की तारीफकी और कहा कि पूर्व पीएम की वजह से करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त हुए। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मनमोहन सिंह की तारीफ की आड़ में चिदंबरम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उनके कार्यकाल में 14 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए, जबकि भाजपा सरकार ने लोगों को गरीबी में धकेल दिया। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ। बीजेपी की वजह से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मोदी पर जमकर बरसे मनमोहन सिंह।

ट्वीट मामले में वीरप्पा मोइली के बेटे हर्षा को कांग्रेस ने दिया नोटिस

बेंगलुरु(आरएनएस)। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के बेटे हर्षा को एक ट्वीट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि ट्वीट में इस बात का जिक्र था कि ठेकेदारों द्वारा पार्टी के टिकट को प्रभावित किया जा रहा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। गौरतलब है कि ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया, जिसमें कहा गया था, कांग्रेस को पैसे की इस राजनीति को सुलझाने की जरूरत है। हम पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ ठेकेदारों की मिली-भगत बर्दाश्त नहीं कर सकते और न ही यह बर्दाश्त कर सकते हैं कि वह इस बात का चुनाव करें कि आगामी चुनावों में उम्मीदवारों का कैसे चयन किया जाए। दरअसल, कहा जा रहा है कि मोइली का यह ट्वीट पीडब्ल्यूडी मंत्री महादेवप्पा पर केंद्रित था, जिन्हें सिद्धारमैया का खास माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोइली का यह ट्वीट विवाद ऐसी खबरों के बीच आया है, जिनमें कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मोइली, एक मीटिंग के दौरान महादेवप्पा द्वारा उनके बेटे हर्षा को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों से हर्षा का पत्ता काटे जाने की तैयारी चल रही है।

बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को पैरेंट्स का विवाद सुलझाने के लिए दिया कार्ड

नइ दिल्ली,(आरएनएस)। सुप्राम काट म आम तार पर कस का सुनवाइ आर फसल हात ह जिस रगा का पारभाषा म कहा जाए ता यह स्याह या सफेद होता है। शनिवार को देश की सर्वोच्च अदालत में थोड़ी रौनक और रंग दिखाई दिए। 7 साल से चल रहे तलाक के केस में दंपती के 10 साल के बेटे ने सभी जजों को हाथ से बनाकर कार्ड दिया और आभार प्रकट किया। सर्वोच्च अदालत के जज बच्चे की इस संवेदनशीलता से भावुक हो गए और खुशी-खुशी उसके दिए तोहफे को स्वीकार किया। जस्टिस कुरियन जोसफ और जस्टिस एम शांतानागोदार ने सुप्रीम कोर्ट की 68 साल पुरानी परंपरा को बदलते हुए मासूम बच्चे के दिए कार्ड को तोहफे के तौर पर रख लिया। बच्चे की संवेदनशीलता ने कोर्ट में मौजूद जजों के साथ सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया। चंडीगढ़ के दंपती की शादी 1997 में हुई थी और इस शादी से दोनों के दो बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी 20 साल की है और छोटा बेटा 10 साल का। वैवाहिक जीवन में खटपट के बाद दोनों ने 2011 में एक-दूसरे से अलग रहना शुरू कर दिया। अलगाव के बाद दंपती के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ 23 आपराधिक केस भी दर्ज करा दिया। दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस लीजा गिल ने भी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गिल के साथ मध्यस्थता की कोशिश करनेवाली वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा की कोशिशों की भी सराहना की। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दोनों पक्षों को चैंबर में बुलाकर मध्यस्थता की कोशिश की और दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग होने और एक-दूसरे के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने के लिए तैयार हो गए। कोर्ट को कोशिशों के बाद भी दंपती की शादी तो नहीं बच सकी, लेकिन दोनों पक्ष आपसी सहमति और सम्मानजनक तरीके से अलग होने के लिए तैयार हो गए। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि बहुत सी खूबसूरत चीजों का अंत होता है, लेकिन पीछे कई कड़वाहटें भी रह जाती हैं। कोर्ट ने बच्चों के पिता को उनकी मां के नाम पंचकूला का एक प्लॉट ट्रांसफर करने और बच्चों के खर्चे के लिए 50 हजार रुपए देने का भी आदेश दिया।

कॉलेजियम के भेजे नामों को ही माने सरकारः कानून विशेषज्ञ

नई दिल्ली,(आरएनएस)। कानून के विशेषज्ञों ने सरकार को आगाह किया है कि वह शीर्ष न्यायालय में नियुक्ति के लिये किसी एक की पदोन्नति रोककर हाई कोर्ट की कलिजयम व्यवस्था के तहत की गयी सिफारिशों में से किसी अन्य की नियुक्ति स्वीकार नहीं करे। उन्होंने ध्यान दिलाया कि भारत के एक प्रधान न्यायाधीश ने कानून मंत्रालय को बताया था कि नियुक्ति के लिये एकसाथ भेजे गये नामों को अलग नहीं किया जाये। सरकार में उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ की नियुक्ति रोककर वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करना चाहता है। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिये न्यायालय की कलिजयम ने जनवरी में इन दोनों नामों की एकसाथ सिफारिश की थी। सरकार का मानना है कि जोसेफके नाम की सिफारिश के दौरान कलिजयम ने वरिष्ठता एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अवहेलना की है। कलिजियम द्वारा वर्ष 2016 में उत्तराखंड से न्यायमूर्ति जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश करने की सिफारिश सरकार ने की गयी थी, लेकिन वह अभी भी लंबित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अप्रैल 2016 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को खारिज कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि कानून के विशेषज्ञों से जब पूछा गया कि कलिजयम की सिफारिशों में से कुछ को लागू कर अन्य को लंबित रखा जा सकता? उन्होंने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा के जून 2014 में लिखे उस पत्र का जिक्र करते हुए सरकार से कहा कि अपने पत्र में प्रधान न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया था कि कलिजयम की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यपालिका इन सिफारिशों को अलग नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति लोढ़ा ने सरकार को उस वक्त पत्र लिखा था जब उसने कोलेजियम की अन्य सिफारिश को स्वीकारते हुए वरिष्ठ वकील एवं पूर्व सलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के विरूद्ध फैसला किया था। बहरहाल इस बीच सुब्रमण्यम ने उच्चतम न्यायालय में अपनी नियुक्ति पर सहमति वापस ले ली थी। शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिये न्यायमूर्ति जोसेफके नाम की सिफारिश के दौरान कलिजयम ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्ति के लिये वह अन्य मुख्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के अन्य वरिष्ठ न्यायमूर्तियों की तुलना में अधिक योग्य और उपयुक्त हैं। उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायमूर्तियों की शीर्ष संस्था ने कहा कि कलिजयम ने मुख्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्याय मूर्तियों की प्रतिभा एवं सत्यनिष्ठा के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर उनकी समग्र वरिष्ठता पर भी विचार किया था।

रेलवे में एयरलाइंस जैसा डायनेमिक प्राइसिंग के सुझाव को रेल मंत्री ने ठुकराया

नई दिल्ली,(आरएनएस)। एयरलाइंस जैसी डायनेमिक प्राइसिंग को रेलवे में भी लागू करने को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नाखुशी जाहिर करते हुए सुझाव को नकार दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, रेल मंत्री ने फ्लेक्सी फेयर स्कीम को रिव्यू करने के लिए बनाई गई कमिटी से फिर से रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। पिछले साल दिसंबर में बनाई गई कमिटी अभी लागू फ्लेक्सी सिस्टम का प्रभाव जानने और रेवेन्यू बढ़ाने के और तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए बनी थी। कमिटी ने 15 जनवरी को अपनी रिपोर्ट भेजी जिसमें सभी एक्सप्रेस मेल ट्रेनों में एयरलाइंस की तरह डायनेमिक प्राइसिंग लागू करने का सुझाव दिया। कमिटी का सुझाव था कि किसी भी टिकट की कीमत कई कारकों पर निर्भर करेगी। जिसमें त्योहारों के समय अधिक रेट, लोअर बर्थ के लिए अतिरिक्त चार्ज, कम समय में पहुंचाने वाली ट्रेन का ज्यादा किराया शामिल था। कमिटी ने सुझाव दिया कि था जिससे ट्रेन का किराया फ्लाइट्स की तरह ट्रेन यात्रा के दिन करीब आने के साथ-साथ बढ़ता जाएगा। 13 मार्च को फ्लेक्सी फेयर को लेकर हुई 20 मिनट की मीटिंग में गोयल ने इन सभी सुझावों को लेकर नाखुशी जाहिर की और कमिटी से फिर से विचार करने को कहा। इस कमिटी में रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारी, नीति आयोग के सलाहकार और एयर इंडिया के कुछ अधिकारी शामिल थे।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन "हेडलबर्ग" से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

C M Y K